

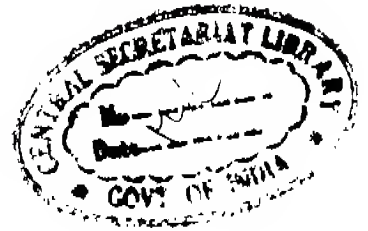


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1996/चैत्र 7, 1918

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1996/CHAITRA 7, 1918

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1996

का. आ. 256 (अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

फरवरी, 1990 में हुए निर्वाचन में महाराष्ट्र राज्य के 170—नाडेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से डा. दास राव देशमुख का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “निर्वाचित अभ्यर्थी” कहा गया है) निर्वाचन, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) धारा 123 के खंड (3) और खंड (3क) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के लिए जाने के आधार पर मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद न्यायपीठ) द्वारा तारीख 18-7-1991 को अपास्त कर दिया गया था ।

एक अपील निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी और उस न्यायालय ने तारीख 20-8-1991 को अंतिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन के संबंध में सशर्त रोक लगा दी थी ।

और उच्चतम न्यायालय ने डा. दास राव देशमुख का निर्वाचित शून्य घोषित करने हुए और डा. देशमुख को उक्त अधिनियम की धारा 123 के खंड (3) और खंड (3क) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण करने का दोषी ठहराते हुए अपील को तारीख 14-7-1995 को खर्च सहित खारिज कर दिया ।

और राष्ट्रपति ने, उक्त अधिनियम की धारा (8क) की उपधारा (3) के अनुसरण में, उस प्रश्न पर कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन निर्गृहीत कर दिया जाता चाहिए और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ।

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय दी है (उपाबंध देखें) कि निर्वाचित अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट

आचरण किए जाने के लिए छह वर्ष की अवधि के लिए, जिसकी संगणना 14 जुलाई, 1995 प्रथीन, उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी, निरहित किया जाना चाहिए।

अतः अब, मैं, गंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क को उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चित करता हूँ कि निर्वाचन अभ्यर्थी को 14-7-1995 से छह वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाए।

नई दिल्ली,

25 मार्च, 1996

भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1995 का निर्देश मामला सं. 2 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश)

निर्देश : डा. दाम राव देशमुख, महाराष्ट्र विधान सभा सदस्य की निरर्हता।

राय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसके पश्चात् 1951 अधिनियम कहा गया है) धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति के इस निर्देश में, इस प्रश्न पर कि क्या डा. दाम राव देशमुख, महाराष्ट्र राज्य विधान सभा का भूतपूर्व सदस्य, को, जिनका विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचन भ्रष्ट आचरण के आधारों पर अपास्त कर दिया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन निरहित किया जाना चाहिए और यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है। संक्षिप्त रूप में कथित सुसंगत तथ्य निम्नलिखित हैं :—

डा. दाम राव देशमुख, जिन्होंने फरवरी, 1990 में 170—नांडेड, निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन लड़ा था। '1951—अधिनियम' की धारा 123 (3) और धारा 123 (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण (उसके धर्म के नाम पर मत के लिए अपील और शत्रुता या घृणा की भावनाओं का नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, आदि के आधार पर संप्रवर्तक) करने का दोषी पाए गए थे और 1990 की निर्वाचन याचिका सं. 8 में उनका निर्वाचन मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद न्यायपीठ) द्वारा तारीख 18-7-1991 के उसके निर्णय द्वारा अपास्त कर दिया गया था। श्री देशमुख ने '1951—अधिनियम' की धारा 116क (2) के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में

एक अपील (1991 की सिविल अपील सं. 3169) फाइल की। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, 28-8-91 को अपील ग्रहण करते समय, आई एम. 2/91 के संबंध में अपने आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के तारीख 18-7-1991 के निर्णय के प्रवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए रोक लगा दिया था :

“श्री दाम राव देशमुख, अपीलार्थी को, जिनका निर्वाचन अपास्त कर दिया गया है, विधान सभा में बने रहने और सदस्यता—रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है और वह इस न्यायालय द्वारा अपील की मुनवाई लेवित रहने और उसका अंतिम रूप से निपटारा किए जाने तक उक्त विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए हक्कादार नहीं होगा।”

उच्चतम न्यायालय ने तारीख 14-7-95 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा 1991 की सिविल अपील सं. 3169 का अंतिम रूप से निपटारा किया और डा. दाम राव देशमुख, अपीलार्थी, का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए और डा. देशमुख का, उनके लिए “मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए” मत देने की अपील करने वाले पोस्टर के प्रदर्शन की अनुज्ञा देने के लिए धारा 123 (3) और धारा 123 (3क) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने का दोषी ठहराते हुए अपील को खर्च सहित खारिज कर दिया।

राष्ट्रपति ने निर्देश के प्राप्त होते पर, आयोग ने, अपनी राय देने से पहले, डा. देशमुख को इस मामले में सुने जाने का अवसर देने का विनिश्चय किया। तदनुसार, डा. देशमुख को स्वयं या उनके सम्पत् रूप से प्राधिकृत काउंसिल द्वारा मुनवाई में उपसंज्ञात होने और अपना निवेदन करने का निर्देश दिया गया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि यदि वह ऐसा चाहें तो इस मामले के संबंध में 7-2-96 को या उसके पूर्व अपना लिखित कथन भेजें। इसके अनुसरण में, डा. देशमुख ने 7-2-96 को अपना लिखित कथन फाइल किया। आयोग द्वारा डा. देशमुख को नियत किए गए अनुसार, तारीख 14-2-1996 को 3 बजे अपराह्न में उनके विधान काउंसिल श्री राज रामाचंद्रन के माध्यम से सुना गया।

डा. देशमुख की ओर से विधान काउंसिल श्री रामाचंद्रन ने अपने मौखिक निवेदन में मुख्य रूप से तारीख 7-2-1996 के लिखित कथन में किए गए अभिवक्तियों को दोहराया। उसने निवेदन किया कि एकमात्र आधार, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने डा. दाम राव देशमुख के निर्वाचन को अपास्त करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को मान्य ठहराया है, यह है कि उन्होंने “अपने निर्वाचन प्रचार के लिए पोस्टर प्रदर्शन-20 प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञात किया था”। उक्त पोस्टर में डा. दाम राव देशमुख के हस्ताक्षर नहीं थे। पोस्टरों के प्रदर्शन किए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डा. देशमुख की मौन सहमति का

निष्कर्ष माना गया और ऐसे निष्कर्ष पर साध्य अधिनियम की धारा 114 पर निर्भर करने हुए पहुँचा गया। उसने अनवरत रूप से यह तर्क दिया कि डा. देशमुख के मामले के तथ्यों की मनोहर जोशी बनाम नितिन बाबुराव पाटिल और अन्य (1996 (1) एस सी सी 169) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की कमीटी पर जांच की जानी चाहिए, जिससे यह प्रकट होगा कि डा. देशमुख का निर्वाचन शुन्य घोषित नहीं किया जा सकता था और यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय और आदेश, जिसने प्रदर्शन 020 के रूप में पोस्टर लगाने का भ्रष्ट आचरण करने का उन्हें दोषी ठहराया, इस समय सुस्थापित विधि की दृष्टि से पोस्टर के प्रदर्शन में अभ्यर्थी की मौन सहमति को उसकी सहमति नहीं माना जा सकता है, डा. देशमुख को "भ्रष्ट आचरण" के लिए दायी नहीं बनाता है, अतः इसका परिणाम "1951 अधिनियम" की धारा 8क के अधीन निरर्हता नहीं हो सकता है।

न्युनीकरण करने वाली परिस्थितियों का अभिवचन करते हुए विद्वान काउंसिल ने यह तर्क दिया कि डा. देशमुख उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं और वृत्ति से क. ना. क. सर्जन हैं, जिन्होंने एम. एस. किया है और यह कि यदि शिक्षित व्यक्तियों को सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बने रहने से हतोत्साहित किया जाता है तो समस्त सोसाइटी को नुकसान पहुँचेगा; डा. देशमुख ने व्यावहारिक रूप से विधान सभा सदस्य के रूप में अपनी प्रास्थिति 1991 से खो दी है और उनका निर्वाचन भी शुन्य ठहराया गया; और यह कि इतना दंड अपने आप में उक्त भ्रष्ट आचरण के अनुपात में नहीं है, अतः सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आगे यह भी तर्क दिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में किया गया यह अभिवाक् कि मान पोस्टर ने तात्त्विक रूप से निर्वाचन को प्रभावित नहीं किया, अतिवादित रह गया है। किसी व्यक्ति की निरर्हता को दल प्रणाली के कार्यकरण और सीमित विवेकाधिकार, जिसका कोई अभ्यर्थी, जब वह किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचन लड़ता है, उपभोग करता है, के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

आयोग ने डा. देशमुख की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा की गई बहस पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। आयोग ने निरंतर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि न्यायालयों के निष्कर्षों को 1951-अधिनियम की धारा 8क के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता या उन पर प्रहार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि आयोग उच्च न्यायालयों या शीर्षस्थ न्यायालय के निष्कर्षों पर निर्णय देने के लिए बैठा है। आयोग निर्वाचन याचिकाओं और निर्वाचन अपीलों में, न्यायालयों के ऐसे निष्कर्षों से उद्भूत निरर्हता के प्रश्न पर विचार करते समय, न्यायालयों के निष्कर्षों का पुनर्जीवन करने की शक्तियाँ अनाधिकार ग्रहण नहीं कर सकता।

विद्यमान प्रस्तुत कार्यवाहियों में, आयोग ने केवल दो प्रश्नों पर, अर्थात्, क्या डा. देशमुख को, जिन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, (i) निरर्हता किया जाना चाहिए, और (ii) यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिए, अपनी राय देने की अपेक्षा की गई है। 1951 अधिनियम की धारा 8क (1) के परन्तुक के अधीन ऐसी अवधि उस तारीख से, जिसको उसके दोषी पाए जाने के निष्कर्ष वाला आदेश प्रभावी होता हो, छह वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती। प्रस्तुत मामले में ऐसी तारीख 14-7-95, अर्थात्, वह तारीख होगी जिसको उच्चतम न्यायालय ने अपना अन्तिम विनिश्चय दिया था, जिसके द्वारा तारीख 18-7-91 के उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाला तारीख 20-8-91 का उसका पूर्ववर्ती अन्तरिम आदेश बातिल हो गया था।

भारत निर्वाचन आयोग

1951—अधिनियम की धारा 8क के अधीन श्री गडख यशवन्त राव कंकरराव की निरर्हता से संबंधित ऐसी ही एक कार्यवाही [1994 का निर्देश मामला सं. 1 (आर पी ए)] में आयोग ने राष्ट्रपति को तारीख 16-5-1994 की अपनी राय में इस प्रकार मत व्यक्त किया था:

"उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते समय, आयोग का कृत्य किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति और गंभीरता के बारे में पता लगाने तक ही सीमित है और क्या ऐसी न्यून और कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं जो एक और कतई कोई निरर्हता अधिरोपित न करने को न्यायोचित ठहराती हों या 1951—अधिनियम की धारा 8(1) के परन्तुक में यथा अनुज्ञेय छह वर्ष की अधिकतम अवधि से कम किसी अवधि के लिए निरर्हता अधिरोपित करने को न्यायोचित ठहराती हों।"

इस प्रकार, विद्यमान कार्यवाहियों में भी आयोग को यह देखना है कि क्या डा. देशमुख अपने पक्ष में कोई न्यून या कम करने वाली परिस्थिति दर्शित करने में समर्थ रहे हैं।

आयोग, स्वयं को, डॉ. देशमुख राव का एक डाक्टर होने का और उनके द्वारा किसी न्यूनकारी तथ्य के रूप में पोस्टर के प्रदर्शन के लिए केवल मौन अनुमोदन दिए जाने के तर्क को, जैसा कि विद्वान काउंसिल दिया गया स्वीकार करने में असमर्थ पाता है। इसके विपरीत, आयोग का यह दृढ़ विचार है कि यह तथ्य कि निर्णय में उल्लिखित प्रकृति का पोस्टर डा. देशमुख द्वारा उनके इतने शिक्षित व्यक्ति होने के बावजूद चुपचाप प्रदर्शित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया था। ऐसे व्यक्तियों के जो उच्च शिक्षा-प्राप्त हैं, अपराध को उल्लेखनीय दण्ड के योग्य बनाता है जिससे सिद्ध भ्रम के आधार पर ऐसे भ्रष्ट आचरण का भविष्य में किसी निर्वाचन प्रचार के दौरान सहारा न लिया जाए।

अष्ट आचरण अपनाने वाले या धर्म के आधार पर अपील करने वाले दल पर रोक लगाने या उस पर नियंत्रण रखने के विषय में किसी राजनैतिक दल के टिकट पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के सीमित विवेकाधिकार का तर्क भी कोई निष्कर्ष निकालने में असफल रहा है। अभ्यर्थी, उस दल में जो उसे प्रायोजित करना है, अलग नहीं होता है। ऐसे सभी फायदों में, जो किसी राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थिता के प्रयोजन में निहित हैं सम्मिलित होते समय अभ्यर्थी दल द्वारा किए गए किसी अतिक्रमण की दशा में, दायित्व या विधि की कठोरता से बचने के लिए ऐसे किसी बहाने की शरण नहीं ले सकता। जब अभ्यर्थी इतना शिक्षित और प्रबुद्ध हो जितना कि डा. देशमुख दावा करते हैं तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचनों की शुद्धता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएगा और धर्म के आधार पर मतों के लिए अपील करने से बचने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में, अभिजात वर्ग अनुगृहीत की धारणा अधिक बलपूर्वक लागू की जानी चाहिए। अतः राजनैतिक दल द्वारा ऐसे आचरणों को रोक्ने में असफलता, अभ्यर्थी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने संप्रेषण में प्रमुख रूप से यह प्रदर्शित किया है कि ऐसे पोस्टर का उपयोग अपने आप में यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) (3क) के अधीन अष्ट आचरण में लिप्त रहा है।”

काउंसिल ने केवल यह और निवेदन किया था कि डा. देशमुख को वस्तुतः विधान सभा में उनके स्थान से 1991 में वंचित किया गया है और यदि निरहंता प्रवर्तित की जाती हो, तो वह कम से कम होनी चाहिए।

आयोग कोई सहायता नहीं कर सकता किंतु यह निष्कर्ष बेता है कि डा. देशमुख द्वारा किया गया अष्ट आचरण, जैसा कि प्रस्तुत मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साबित कर दिया गया है, गंभीर प्रकृति का है। धर्म के आधार पर अपने पक्ष में मत देने के लिए मतदाताओं को अपील कराना और “मुसलमानों को सबक सिखाना” घृणा की भावना नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के आधार पर पैदा करने के लिए नियोजित कार्य के अलावा कुछ नहीं है। डा. देशमुख ने मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी धार्मिक मनोवृत्ति और जोश का उकसाया है जिससे उनके निष्पक्ष निर्णय, ताकि विचार और सही पूर्वानुमान प्रभावित हुए हैं तथा ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में उसके गुण से अन्यथा विचारों पर मत देने के लिए प्रेरित किया है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि ऐसे हातिकाकर आचरणों पर जो बहुत ही खतरनाक हैं और हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकते हैं, गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कड़ाई से दबा दिया जाना चाहिए। ऐसे घृणित आचरणों में लिप्त और उन्हें चुपचाप स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम शास्ति दी जानी

चाहिए क्योंकि उनके प्रति बरती गई नरमी से यह अभिप्रेत होगा कि उन अष्ट आचरणों के साथ समझौता किया जाता है जो निर्वाचनों की शुद्धता को दूषित करते हैं।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आयोग की यह राय है कि और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता है कि डा. दास राव देशमुख को ऊपर वर्णित अष्ट आचरण करने के लिए निरहंत किया जाना चाहिए और उसकी निरहंता उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख, अर्थात् 14-7-95 से छह वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बनी रहनी चाहिए, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (1) के परन्तुक में उपबंधित है।

राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश उपरोक्त आण्य की आयोग की राय के साथ लौटाया जा रहा है।

ह/-	ह/-	ह/-
(जी. बी. जी. कृष्णमूर्ति)	(टी. एन. जेपन)	(एम. एस. गिल)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली

तारीख : 27 फरवरी, 1996

[फा. सं. 7/10/96-वि. 2]
पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1996

S. O. 256(E).—The following Order made by the president is published for general information:—

ORDER

Whereas the election of Dr. Das Rao Deshmukh (hereinafter referred to as the 'returned candidate') from 170-Nanded Assembly Constituency in the State of Maharashtra at the election held in February, 1990 was set aside by the High Court of Bombay (Aurangabad Bench) on 18-7-1991 on the ground of commission by the returned candidate of corrupt practice specified in clauses (3) and (3A) of section 123 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951) (hereinafter referred to as "the said Act"):

Whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court by an interim order on 20-8-1991 granted a conditional stay of the operation of the judgement of the High Court.

And whereas the Supreme Court dismissed the appeal on 14-7-1995 with costs declaring the election of Dr. Das Rao Deshmukh as void and holding Dr. Deshmukh guilty of committing corrupt practice specified in clauses (3) and (3A) of section 123 of the said Act;

And whereas the president has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the returned candidate should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above, for a period of six years to be reckoned from 14th July, 1995 i.e. the date of the order of the Supreme Court.

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act, do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from 14-7-1995.

New Delhi,

25th March, 1996.

PRESIDENT OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 2 (RFA) of 1995.

(Reference from the President under Section 8A of the Representation of the People Act, 1951).

In re: Disqualification of Dr. Das Rao Deshmukh, a member of the Maharashtra Legislative Assembly.

OPINION

In this Reference from the president under Section 8A (3) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act'), opinion of the Election Commission has been sought on the question as to whether Dr. Das Rao Deshmukh a former member of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, whose election as MLA has been set aside on grounds of corrupt practice, should be disqualified and, if so, for what period under Section 8A(1) of the said Act.

The relevant facts, briefly stated, are as follows:-

Dr. Das Rao Deshmukh who contested the general election to Maharashtra Legislative Assembly from 170 Nanded Constituency in February 1990, was found guilty of having committed corrupt practice under Section 123(3) and 123(3A) of the 1951-Act (Appeal for vote in the name of his religion and promotion of feelings of enmity or hatred between different classes of citizen on grounds of religion, race etc.) and his election was set aside by the High Court of Bombay (Aurangabad Bench) in Election Petition No. 8 of 1990 vide its Judgment dated 18-07-1991. Shri Deshmukh filed an appeal in the Supreme Court (Civil Appeal No. 3169 of 1991) against the judgment of the High Court under section 116A (2) of the '1951-Act'. The operation of the judgment of the High Court dated 18-07-1991 was stayed by the Hon'ble Supreme Court while admitting the appeal 20-8-91 by its order on IA No. 2/91, subject to the following conditions:—

"Shri Das Rao Deshmukh the Appellant whose Election has been set aside be and is hereby permitted to sign the Register of Membership in the Legislative Assembly and shall not be entitled to act as a member of the said Assembly pending the hearing and final disposal by this Court of the appeal".

The Supreme Court finally disposed of the Civil Appeal No. 3169 of 1991 vide its Judgment and order dated 14-7-95 and dismissed the appeal with costs declaring the election of Appellant, Dr. Das Rao Deshmukh as void and holding Dr. Deshmukh guilty of committing corrupt practice under Section 123 (3) and 123 (3A) for permitting the display of a poster with an appeal to vote for him 'to teach the Muslims a lesson'.

On receipt of the Reference from the president, the Commission, before tendering its opinion decided to afford Dr. Deshmukh an opportunity of being heard in the matter. Dr. Deshmukh was accordingly directed to appear at the hearing either in person or through his duly authorised counsel and make his submissions. He was also directed to send his written statement, if he so desired, in the matter on or before 7-2-96. In pursuance of the same Dr. Deshmukh filed his Written Statement on 7-2-96.

Dr. Deshmukh was heard through his learned Counsel, Shri Raju Ramachandran, by the Commission on 14-02-1996 at 3.00 p.m., as scheduled.

In his oral submissions, the learned Counsel for Dr. Deshmukh, Shri Ramachandran mainly reiterated the pleadings made in the Written Statement dated 07-02-1996. He submitted that the only ground on which the Hon'ble Supreme Court has upheld the judgment of the High Court setting aside

the election of Dr. Das Rao Deshmukh is that he had "permitted to display poster exhibit 20 for the purpose of his election campaign". The said poster did not carry the signature of Dr. Das Rao Deshmukh. The finding of the tacit consent of Dr. Deshmukh was assumed by Hon'ble High Court for displaying the posters and such finding was arrived at by placing reliance on section 114 of Evidence Act. He strenuously argued that the facts of the case of Dr. Deshmukh may be tested on the touch-stone of law since declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Manohar Joshi Vs. Nitin Baburao Patil and Another [1996 (1) SCC, 169] from which it would appear that the election of Dr. Deshmukh could not have been declared void and that the judgment and order of Hon'ble Supreme Court which held him guilty of committing corrupt practice qua poster as exhibit 020 does not render Dr. Deshmukh liable for "corrupt practice" in view of the law settled now; that the tacit consent of the candidate in the display of the poster cannot be taken as his consent & hence cannot result in disqualification under section 8A of the 1951 Act.

Pleading extenuating circumstances, the learned Counsel argued that Dr. Deshmukh is a highly educated person & an ENT Surgeon by profession having done M.S. and that the society at large will be put to disadvantage if educated persons are discouraged from being in active political and social life; that Dr Deshmukh practically lost his status as MLA since 1991 and his election was also held void; and that this much punishment in itself was disproportionate to the said corrupt practice and hence a sympathetic view may be taken. It was also further argued that, the plea taken by the candidate in the High Court that the poster itself did not materially affect the election has remained uncontroverted. Disqualification of an individual ought to be viewed in the context of the functioning of the party system, and the limited discretion which a candidate enjoys when he contests on the ticket of a political party.

The Commission has carefully considered the arguments submitted by the learned Counsel on behalf of Dr. Deshmukh. The Commission has consistently taken the view that the findings of the Courts cannot be questioned or assailed before the Commission in the proceedings under Section 8A of the 1951-Act as that would tantamount to the Commission sitting in judgment over the findings of the High Courts or the Apex Court. The Commission cannot arrogate to itself the powers of the review of findings of the Courts in the election petitions and election appeals, while considering the question of disqualification arising out of such findings of the Courts.

In the present proceedings, the Commission is called upto to tender its opinion only on two questions,

namely; whether Dr. Deshmukh, who has been found guilty of corrupt practice by the High Court and the Supreme Court (i) should be disqualified, and (ii) if so, for what period. Under the Proviso to Section 8A(1) of the 1951-Act, such period cannot exceed six years from the date on which the order of the Court finding him guilty takes effect. In the present case such date will be 14-07-1995, i.e., the date on which the Supreme Court gave its final decision and whereby its earlier interim order dated 20-8-91 staying the operation of the High Court's order dated 18-7-91 stood vacated.

In a similar proceeding under Section 8A of the 1951-Act relating to disqualification of Shri Gadakh Yashwant Rao Kankarrao [Reference case No. 1 (RPA) of 1994], the Commission in its opinion dated 16-05-1994 to the President observed:

"While considering the above questions, the Commission's function is limited to look into the nature and gravity of the corrupt practice committed and whether there is any extenuating and mitigating circumstances which may justify either the imposition of no disqualification at all, as one extreme, or the imposition of disqualification for a period lesser than the maximum period of six years as permissible under the proviso to section 8 (1) of 1951-Act."

In the present proceedings also, the Commission has thus to see whether Dr. Deshmukh has been able to show any extenuating or mitigating circumstance in his favour.

The Commission finds itself unable to be persuaded by the argument of either Dr. Deshmukh Rao being a Doctor and having allowed only a tacit approval to the display of the poster as being any extenuating factor, as urged by the learned Counsel. On the contrary, the Commission is of the firm view that the fact that poster of the nature adverted to in the judgment had been allowed to be exhibited by Dr. Deshmukh, albeit tacitly, despite his being so highly qualified should, if anything, make the offence of such persons as are highly educated, deserving of exemplary punishment so that recourse to such corrupt practices on the basis of religion are not resorted to in future during an election campaign.

The argument of limited discretion of a candidate contesting on the ticket of a political party in the matter of curbing or putting a check on the party resorting to corrupt practices or appealing on grounds of religion also fails to cut ice. The candidate does not stand alone from the party which sponsors him. While part-taking of all the benefits that the

sponsorship of candidature by a political party implies, the candidate cannot at the same time escape the liability or the rigours of the law, in the event of any violation committed by the party by taking shelter behind such a subterfuge. When the candidate happens to be as educated and enlightened a person as Dr. Deshmukh claims and is expected to be, the responsibility for ensuring purity of elections and steering clear of any attempts at appeal for votes on the basis of religion increases all the more. The concept of noblesse oblige' applies in such cases with redoubled vigour. Failure to contain such practices by the political party should therefore bring forth its repercussions upon the candidate. As much has also been highlighted by the Supreme Court in its observation that "the use of such a poster by itself is sufficient to hold that the appellant had indulged in corrupt practice in section 123 (3) of (3A) of Representation of the People Act, 1951."

The only other submission of the Counsel was that Dr. Deshmukh had been virtually deprived of his seat in the legislative assembly since 1991 and the disqualification if enforced should be minimum.

The Commission cannot help but conclude that the corrupt practice committed by Dr. Deshmukh as having been proved by the Hon'ble Supreme Court in the present case are of grave nature. Allowing Appeal to be made to the voters to vote in his favour on the ground of religion and to teach Muslims a lesson' is nothing but an Act calculated to create feelings of hatred between different classes of citizens on religious grounds. Dr. Deshmukh has thereby acquiesced in the playing upon the religious sentiments of the voters and arousing their religious passions and fervors which blur their dispassionate judgment, rational thinking and right

perceptions and motivate them to vote for a candidate on considerations other than his merit. There cannot be two opinions that such pernicious practices which are highly dangerous and can threaten the very survival of our democracy must be viewed with the utmost concern and put down with a heavy hand. Persons indulging in and acquiescing in such nefarious practices must be visited with the severest penalty permissible under the law as any leniency shown to them would mean compromising with those corrupt practices which sully the purity of elections.

Having regard to the above, the Commission is of the opinion, and accordingly holds that Dr. Das Rao Deshmukh should be disqualified for having committed corrupt practices mentioned above. Further, his disqualification should run for the maximum period of six years from the date of the order of the Supreme Court namely 14-7-95, as provided under the proviso to sub-section 1 of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

The reference received from the President is returned with the Commission's opinion to the above effect.

(G.V.G. KRISHNAMURTHY)
Election Commissioner

(T.N. SESHAN)
Chief Election Commissioner

(M.S. GILL)
Election Commissioner

New Delhi

Dated : 27th February, 1996.

[F. No. 7(10)/96-Leg.II]
P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

